

रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित।

शिमला, मंगलवार, 31 जनवरी, 1984/11 भाष्म, 1905

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 जनवरी, 1984

क्रमांक एल० एल० आर० -डी० (6) 17/83.—हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट अष्टावार आचरण निवारण विधेयक, 1983 (1983 का विधेयक संख्यांक 23) जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा “भारत के संविधान के अनुच्छेद 201” के अन्तर्गत

दिनांक 31-1-84 को स्वीकृत किया गया, को संविधान के अनुच्छेद 348(3) में अपेक्षित अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र हिमाचल प्रदेश में 1984 का अधिनियम संख्याक 3 के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

वेद प्रकाश भट्टनागर,
सचिव (विधि)।

1984 का अधिनियम संख्यांक 3.

हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983

राज्य या लोक उपकरणों या स्थानीय प्राधिकरणों, सहकारी समितियों या राज्य सरकार से सहायता प्राप्त या द्वारा स्थापित अन्य संस्थाओं या संगठनों के कार्यों के सम्बन्ध में सेवारत व्यक्तियों द्वारा और राज्य सरकार और उपर्युक्त निकायों के साथ व्यवहार में कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा अपनाये गये विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण के उन्मूलन और प्रभावकारी निवारण के उद्देश्यों से उनमें लगे व्यक्तियों को दण्डित करने तथा उनसे सम्बद्ध अन्य प्रकीर्ण विषयों के लिए उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौतीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

- | | |
|--|--|
| <p>1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 है।</p> <p>(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।</p> <p>(3) यह 1983 के अक्तूबर के अठाईसवें दिन से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।</p> <p>2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—</p> <p>(क) ‘स्थानीय प्राधिकरण’ से कोई लोक उपकरण, प्राधिकरण, सहकारी समिति, नियम, निकाय, बोर्ड, समिति या संगठन अभिप्रेत है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो कि—</p> <p>(i) राज्य सरकार द्वारा निगमित या स्थापित किया गया है, या</p> <p>(ii) राज्य सरकार की किसी विधि, अध्यादेश, अधिनियम, नियम या विनियम के अधीन गठित किया गया है, या</p> <p>(iii) किसी केन्द्रीय अधिनियम, ग्राम्यादेश, नियम या विनियम के अधीन गठित किया गया है, जिस पर राज्य सरकार का नियन्त्रण और प्राधिकार है;</p> | <p>संक्षि प्त नाम
विस्तार और
प्रारम्भ।</p> <p>परिभाषाएं।</p> |
|--|--|

(ख) "अधिकारी" से राज्य, स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार से सहायता प्राप्त करने वाली या द्वारा स्थापित अन्य किसी संस्था या संगठन के कार्यों के सम्बन्ध में सेवारत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ग) "लोक उपकरण" से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थात् अन्तर्गत कोई सरकारी कम्पनी, जिसमें समादत्त शेयर पूँजी का इकावन प्रतिशत से अध्यून राज्य सरकार द्वारा धारित है, या ऐसी कम्पनी की समनुपांगी कम्पनी जिसमें समादत्त शेयर पूँजी का इकावन प्रतिशत से अध्यून राज्य सरकार द्वारा धारित हो, अभिप्रेत है और कोई निगम या अन्य कानूनी नियाय चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जो प्रत्येक दशा में राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में है, और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व और नियंत्रणाधीन की कम्पनी के अतिरिक्त की कोई ऐसी सरकारी कम्पनी जिसमें राज्य सरकार ने साधारण अभिदाय किया है, भी इसके अन्तर्गत है।

अध्याय 2

संकर्म से सम्बन्धित अपराध

परिभाषाएं।

3. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "संनिर्माण" से संकर्म के संनिर्माण से सम्बन्ध रखने वाले सभी किया-कलाप अभिप्रेत हैं और उत्खनन, भराई, समतलन तथा अन्य सम्बद्ध किया-कलाप भी इसके अन्तर्गत हैं ;

(ख) "ठेकेदार" से संकर्म के सम्बन्ध में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो संविदा के अनुसार उसे निर्माण विभाग के अधीन संकर्म के निष्पादन के लिए जिम्मा लेता है और जहां संदर्भ से अपेक्षित हो, ऐसे संकर्म के निष्पादन के लिए उस द्वारा नियोजित या उसके नियंत्रण में कार्य कर रहे उप-ठेकेदार और सभी अन्य अधिकरण तथा व्यक्तिगण भी इसके अन्तर्गत हैं और पद "संकर्म संविदा" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(ग) "प्रभारी अधिकारी" से संकर्म संविदा के अधीन, संकर्म के सम्बन्ध में ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो फि संकर्म के स्थान पर मूल्यतः और प्रत्यक्षतः यह देखने के लिए उत्तरदायी है फि संकर्म या संकर्म का विनिदिष्ट संभाग संकर्म संविदा के निबन्धनों, शर्तों और विनिर्देशों तथा पर्यवेक्षण अधिकारियों या निर्माण विभाग द्वारा, समय-समय पर, निर्गत निर्देशों, अनुदेशों या संकर्म आदेश के अनुसार सम्यक् रूप से निष्पादित किया जाता है ;

(घ) "निर्माण विभाग का अधिकारी" से ऐसा अधिकारी जो निर्माण विभाग में नियोजित है तथा सर्वेक्षण, संनिर्माण, मूल्यमत्त, अनुरक्षण, पर्यवेक्षण, योजना, ग्रारेखण, रूपांकन, क्रय, सामग्री की आपूर्ति, या भण्डारण, यत्क्रमोदित या विद्युत मंचालित सभी प्रकार की गाड़ियों, संयंत्र, मशीनरी, औजार, पुर्जे या अन्य सारी सामग्री या उपकरणों से सम्बद्ध है, अभिप्रेत है, चाहे पद-नाम कुछ भी हो, और संकर्म के सम्बन्ध में वित्तों और अधिकारिय के संदाय के लिए उत्तरदायी अधिकारी या पदधारी भी इसके अन्तर्गत हैं ;

1956 का

- (३) "पर्यवेक्षण अधिकारी" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसका कर्तव्य निर्माण विभाग में लाग निर्देशिका में अन्तर्विष्ट अनुदेशों या समय-समय पर, निर्माण विभाग द्वारा निर्गत किए हों आदेशों या निर्देशों में अन्तर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार संकर्म का पर्यवेक्षण करता है;
- (४) "संकर्म" से किसी भवन, अधिमंत्रना, बांध, बंधारा, नहर, जलाशय, झील, सड़क, पुल, पुलियां, नलकूप सहित कुंआ, कारखाना, कर्मशाला, जल-प्रदाय प्रणाली, विद्युत संस्थापन प्रणाली या अन्य किसी संकर्म, जिसे राज्य सरकार इस सम्बन्ध में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, वे सर्वेक्षण, संनियार्ण, मुरम्मत या अनुरक्षण से सम्बद्ध कोई संकर्म अभिप्रेत है और उपर्युक्त किसी संकर्म के निर्माण, अनुरक्षण या मुरम्मत से सम्बन्धित सर्वेक्षण, योजना, आरेखण, रूपांकन, क्रय, सामग्री की आपूर्ति या भण्डारण, घंटनोदित या विद्युतचालित सभी प्रकार की गाड़ियां, संयंत्र, मशीनरी, श्रोजार, पुर्जे या अन्य सभी सामग्री और उपकरण भी इसके अन्तर्गत हैं;
- (५) "निर्माण विभाग" से राज्य सरकार का विभाग, लोक उपक्रम, स्थानीय प्राधिकरण, या हिमाचल प्रदेश सहानुभावी समिति अधिनियम, 1968 के अधीन पंजीकृत सहकारी समिति अभिप्रेत है जो संकर्म संविदा देता है या जिसके आदेशों, निर्देशों या नियंत्रण के अधीन संकर्म संविदा की जाती है या संकर्म किया जाता है और—
- राज्य सरकार से पर्याप्त सहायता प्राप्त संस्था या संगठन जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट न हो, और
 - राज्य सरकार द्वारा निगमित या स्थापित कोई कानूनी या अकानूनी निकाय भी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, इसके अन्तर्गत है।

4. जो कोई भी, निर्माण विभाग के साथ की गई संकर्म संविदा का ठेकेदार होते हुए, आशय से, जानबूझ कर या भ्रष्ट हेतु से संविदा के निवन्धनों के तात्त्विक उल्लंघन में या निर्माण विभाग या इसके अधिकारियों द्वारा दिए गए मानकों, विनिर्देशों, आदेशों या निर्देशों की ओर अवहेलना करके इस प्रकार संकर्म का निष्पादन करता है जिससे कि संकर्म या इसके सम्भाग की गणवता, कारोगरी, मजबूती या टिकाऊपन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमनि से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

5. जो कोई भी, संकर्म संविदा के अधीन ठेकेदार द्वारा या अन्यथा निष्पादित किए जा रहे संकर्म का प्रभारी अधिकारी होते हुए आशय से या जानबूझ कर—

- संविदा के निवन्धनों के तात्त्विक उल्लंघन में, या
 - निर्माण विभाग या इसके अधिकारियों द्वारा दिए गए मानकों, विनिर्देशों, आदेशों या निर्देशों की ओर अवहेलना करते हुए संकर्म की—
- करने की अनुज्ञा या मौनानुमति देता है, या
 - उसे रोकने या उसके बारे में रिपोर्ट करने में चूक करता है, या
 - भ्रष्ट हेतु से उसे दुष्प्रेरित करता है,

संविदा आदि के उल्लंघन के लिए ठेकेदार को दण्ड।

पर्यवेक्षण के अभाव के लिए प्रभारी अधिकारी को दण्ड।

जिससे संकर्म या उसके सम्भाग की गुणवता, कारीगरी, मजबूती या टिकाऊपन पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, तो दोनों में से एक प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमनि से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

मिथ्या या
काल्पनिक
मस्टर-रोल
या माप-बही
तैयार करने
के लिए दण्ड।

6. (1) जो कोई भी, संकर्म का प्रभारी अधिकारी होते हुए या लोक निर्माण विभाग का अधिकारी होते हुए, संकर्म के सम्बन्ध में आशय से या जानबूझ कर—

- (क) मिथ्या या काल्पनिक मस्टर-रोल तैयार करता है, या
- (ख) मिथ्या या काल्पनिक माप-बही तैयार करता है, या
- (ग) मिथ्या या काल्पनिक लीड या धातु, रेत, मिट्टी के मिथ्या या काल्पनिक उत्खनन के लिए संदाय करता है, या
- (घ) उत्खनन के अधीन स्तर का उच्चतर दर पर संदाय करने के लिए गत वर्गीकरण करता है, या
- (ङ) बिना संकर्म के या अपर्याप्त या काल्पनिक या नकली संकर्म के लिए संदाय करता है, या
- (च) नियमों और आदेशों के उल्लंघन में ऐसी दरों पर संदाय करता है, जो विल्कुल अनुपयुक्त हैं या जानबूझ कर अधिक संदाय करता है,

तो उसे दोनों में से एक प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमनि से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

(2) जो कोई भी, पर्यवेक्षण अधिकारी होते हुए, उप-धारा (1) के अधीन अपराध करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा उसे भी, दोनों में से एक प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमनि से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

आपूरित
सामग्री की
ठेकेदार द्वारा
गृह्णित बिक्री के
लिए दण्ड।

7. जो कोई भी, संकर्म संविदा के अधीन ठेकेदार होते हुए, निर्माण विभाग द्वारा विनिर्देश के अनुसार संकर्म के लिए आपूरित सीमेण्ट, स्टील, लोहे या अन्य सामग्री को संकर्म में उचित रूप से प्रयोग करने के स्थान पर या बचे हुए सामान को निर्माण विभाग को वापिस करने के स्थान पर, बेचता है या अन्यथा अन्तरित करता है, तो उसे दोनों में से एक प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमनि से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

छलपूर्ण
निविदाएं
देने के लिए
दण्ड।

8. जो कोई भी, निर्माण विभाग के अधीन संकर्म के लिए निविदाकार होते हुए,—

- (क) मिथ्या या अविद्यमान या नकली व्यक्ति के नाम पर काल्पनिक प्रतियोगात्मक निविदाएं प्रस्तुत करके, संकर्म संविदा के अधीन अपने लिए या अन्य व्यक्ति के लिए संकर्म उपाप्त, या प्राप्त करता है या उपाप्त या प्राप्त करने का प्रयास करता है, या
- (ख) दुस्सन्धिपूर्ण निम्न दर निविदा की स्वीकृति के प्रयोजनार्थ प्रतियोगिता से बचने के लिए किसी अन्य निविदाकार या निविदाकारों के साथ मिल कर बड़यन्त्र करता है, या
- (ग) निविदा स्वीकृत करने का प्राविकार रखने वाले अधिकारी पर, अनुचित प्रभाव डलवाने के लिए निकट रिस्तेदार या किसी अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति को इसमें लगाता है या उसका सक्रिय सहयोग लेता है,

तो उसे दोनों में से एक प्राप्त के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमनि से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

स्थष्टीकरण.—इस धारा में निकट रिश्तेदार से पुत्र, पोता, पिता, माता, पत्नी, भाई, बहिन, बहनोई, साला, ससुर और सास अभिप्रेत हैं।

9. जो कोई भी, निर्माण विभाग की ओर से निविदा स्वीकृत करने के लिए छलपूर्ण निविदा को स्वीकृत करने प्राधिकृत अधिकारी होते हुए,—

(क) ऐसी निविदा को स्वीकृत करके या स्वीकृत करने की सिफारिश करके धारा 8 के अधीन अपराध करने की दुष्प्रेरणा करता है, या

(ख) किसी विशेष निविदाकार को लाभान्वित करने के उद्देश्य से, बेईमानी से, निविदाओं के मूल्यांकन का छल साधन करता है,

तो वह दोनों में से एक प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

10. जो कोई भी, निर्माण विभाग का अधिकारी होते हुए, निर्माण विभाग को पर्याप्त हानि पहुँचाते हुए भण्डार से सामान, संयंत्र, मशीनरी, औजार, पुर्जे या अन्य सामग्री और उपकरणों का बेईमानी से सदोषपूर्वक या कपटपूर्वक—

(क) निपटान या अन्यथा अन्तरण करता है, या

(ख) अप्राधिकृत उपयोग की अनुज्ञा देता है,

तो उसे दोनों में से एक प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

11. जो कोई भी, सामान, संयन्त्र, मशीनरी, औजार, पुर्जे या अन्य सामग्री या उपकरणों की आपूर्ति के लिए ठेकेदार होते हुए,—

(क) आपूर्ति की गई मात्रा के सम्बन्ध में दुर्व्यपदेशन करता है, या

(ख) घटिया सामान, संयन्त्र, मशीनरी, औजार, पुर्जे या अन्य सामान या उपकरणों की आपूर्ति करता है जो कि वाणिज्यिक गुणवत्ता के नहीं है या आपूर्ति आदेश में दिए गए नमूनों या विनिर्देशों के अनुसार नहीं है,

तो उसे दोनों में से एक प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

12. जो कोई भी, आपूर्ति के लिए उसे दिए गए आदेश के अनुसरण में ठेकेदार द्वारा की गई आपूर्ति को स्वीकृत करने का प्राधिकार रखने वाला लोक निर्माण विभाग का अधिकारी होते हुए, जानबूझ कर सामान, संयन्त्रों, मशीनरी, औजार, पुर्जे या अन्य सामान या उपकरणों की आपूर्ति को स्वीकृत करके, धारा 11 के अधीन दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण करता है, तो उसे दोनों में से एक प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

निर्माण विभाग के अधिकारियों को धारा 11 के अधीन अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दण्ड।

13. जो कोई भी, निर्माण विभाग का अधिकारी होते हुए, असद्भावपूर्ण इरादे से, खरीद आदेश को इस आशय से खण्डित करता है कि वह ऐसी खरीद कर सके जो अन्यथा उसके वित्तीय प्राधिकार की सीमा से परे होती या सामान, संयन्त्र, मशीनरी, औजार, पुर्जे या अन्य सामान या उपकरणों की खरीद की स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए ऐसी खरीद

खरीद आदेशों को खण्डित करने के लिए दण्ड।

कर सके, तो उसे दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमनि से, अथवा दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

अध्याय 3

बन एवं वन्य प्राणी परिरक्षण से सम्बद्ध अपराध

बन उपज की अवैध कटाई या निपटान के लिए दण्ड।

14. जो कोई भी, बन परिरक्षण या अनुरक्षण या बन उपज के निपटान की अधिकारिता रखने वाला प्रभारी अधिकारी होते हुए, आशय से या जानबूझ कर वाणिज्य के प्रयोजनार्थ,—

- (क) वृक्षों की अवैध कटाई या कुन्दों की निकासी, या
- (ख) अवैध घेराबन्दी या छेवन, या
- (ग) काठ, इमारतों लकड़ी या बांस या अन्य उपज की चोरी,

की अनुज्ञा या मौनानुमति प्रदान करता है या दुष्प्रेरित करता है या रिपोर्ट करने में असफल रहता है तो उसे दोनों में से एक प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि कम से कम एक वर्ष होगी, परन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डित किया जाएगा और जुमनि के लिए भी दायी होगा :

परन्तु न्यायालय अभिलिखित विशेष कारणों से एक वर्ष से कम अवधि के कारावास का दण्डादेश भी अधिरोपित कर सकेगा।

बिना लेखे-जोखे की कातिपय बन उपज के व्यापार के लिए दण्ड।

15. जो कोई भी, किसी बन उपज का व्यापार करता है और जिसके काजे में ऐसी बन उपज है या रही है जिसका वह संतोषपूर्ण लेखा-जोखा नहीं दे सकता है, तो वह दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि कम से कम एक वर्ष होगी, किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुमनि के लिए भी दायी होगा :

परन्तु न्यायालय अभिलिखित विशेष कारणों से एक वर्ष से कम अवधि के कारावास का दण्डादेश भी अधिरोपित कर सकेगा।

स्पष्टीकरण :—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

- (क) “बन उपज” से भारतीय बन अधिनियम, 1927 की धारा 2 के खण्ड (6) और (7) में यथा परिभ्राष्ट “इमारतों लकड़ी और वृक्ष” अभिप्रेत हैं और बिरोजा, कत्था और कोई अन्य बन उपज, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, इसके अन्तर्गत हैं ; और
- (ख) “बन उपज का व्यापार” से किसी रीति, प्रकार या रूप से चाहे वह कुछ भी हो, किसी बन उपज की बिक्री या क्रय या अभिलाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई कारोबार करना, अभिप्रेत है।

16. जो कोई भी अधिकारी होते हुए,—

- (1) बन उपज की नीलामी से सम्बन्धित बोली-पत्रक का छल साधन करता है, या
- (2) किसी व्यक्ति को लाभान्वित करने या सरकारी विभाग को सदोष हानि पहुंचाने के उद्देश्य से काल्पनिक अभिवहन-पास जारी करने का छल साधन करता है ;

1927 का 16

बोली-पत्रक के मिथ्या-करण और अभिवहन-पास के छल साधन के लिए दण्ड।

तो वह दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

17. जो कोई भी, निजी वनों में पेड़ों की कटाई के प्रयोजन के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए निजी और सरकारी वनों की सीमाओं के सीमांकन के लिए उत्तरदायी अधिकारी होते हुए आशय से या जानबूझ कर सरकार को हानि पहुंचाते हुए सदोष सीमांकन करता है तो वह दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि कम से कम एक वर्ष होगी, किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा:

परन्तु न्यायालय, अभिलिखित विशेष कारणों से एक वर्ष से कम अवधि के कारावास का दण्डादेश भी अधिरोपित कर सकेगा।

18. जो कोई भी, बन्ध प्राणियों के परिरक्षण और संरक्षण के लिए कर्तव्यवद्ध अधिकारी होते हुए,—

- (क) बन्ध पशुओं का अवैध आखेट करता है, अनुज्ञा देता है, मौनानुमति देता है या दुष्प्रेरणा देता है; या
- (ख) आखेट-चोरों को आश्रय देता है; या
- (ग) सुगमता से आखेट करने के लिए झुण्ड में एकत्र करने के उद्देश्य से पशुओं को घेर कर लाने या बन्ध पशुओं के आवास-स्थान में आग लगाने के प्रबन्ध में सहायता करता है; या
- (घ) बन्ध-प्राणियों के अवैध आखेट या बन्ध-प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में उल्लिखित बन्ध-प्राणियों के पशु-पदार्थ या प्रतीक के अवैध कब्जे की सूचना को गुप्त रखता है या उसकी रिपोर्ट दर्जने में असफल रहता है;

बन्ध प्राणियों के अवैध आखेट या निर्वाचन के लिए दण्ड।

बन्ध प्राणियों के अवैध आखेट या निर्वाचन के लिए दण्ड।

तो वह दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि कम से कम एक वर्ष होगी, किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डित किया जायेगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा :

परन्तु न्यायालय, अभिलिखित विशेष कारणों से एक वर्ष से कम अवधि के कारावास का दण्डादेश भी अधिरोपित कर सकेगा।

अध्याय 4

अस्पताल आदि से सम्बन्धित अपराध

ओषधियों या चिकित्सीय उपकरणों के दुर्विनियोग या हटाए जाने के लिए दण्ड।

19. जो कोई भी सरकारी अस्पताल, औषधालय या सरकार द्वारा संगठित या सहायता प्राप्त किसी अन्य ऐसी संस्था या केन्द्र में औषधियों या चिकित्सीय उपकरणों के स्टाक-रजिस्टर, बिल या वात्तचर रखने के लिए कर्तव्यवद्ध अधिकारी होते हुए उनका दुर्विनियोग करता है या कपटपूर्वक औषधियों या चिकित्सीय उपकरणों को हटाता है या आशय से या जानबूझ कर ऐसे दुर्विनियोग या हटाए जाने की अनुज्ञा देता है, मौनानुमति देता है या दुष्प्रेरणा करता है तो वह दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि कम से कम एक वर्ष होगी, किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डित किया जायेगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा:

परन्तु न्यायालय अभिलिखित विशेष कारणों से एक वर्ष से कम अवधि के कारावास का दण्डादेश भी अधिरोपित कर सकेगा।

काम से अनु-पस्थिति या कपटपूर्वक या अप्राधिकृत रूप से फीस लेने के लिए दण्ड।

समुचित रूप से अभिलेख नहीं रखने के लिए दण्ड।

श्रीषधियों की कपटपूर्ण खरीद के लिए दण्ड।

20. जो कोई भी, सरकारी अस्पताल, श्रीषधालय या सरकार द्वारा संगठित या सहायता प्राप्त किसी अन्य ऐसी संस्था या केन्द्र का चिकित्सा अधिकारी, कम्पाउण्डर, इंसर या नर्स या कोई अन्य कम्बाचारी होते हुए बिना युक्तियुक्त कारण से और प्राधिकारी को सम्यक रूप से सूचना दिए बिना काम से अनुपस्थित रहता या रहती है या कपटपूर्वक या अप्राधिकृत रूप से किसी व्यक्ति से उसके उपचार के लिए फीस लेता है या लेती है तो उसे दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

21. जो कोई भी, आधात-रिपोर्ट या शब-परीक्षा रिपोर्ट, या रोगी का बैड-हैड टिकट तैयार करने के लिए कर्तव्यबद्ध होते हुए, कपटपूर्वक उसे गलत ढंग से तैयार करता है या सभी व्योरों का उल्लेख नहीं करता है या नियम या विनियम या सरकारी आदेश या परिपत के अधीन उसके लिए ऐसी सूचना देना अपेक्षित होने पर भी प्राधिकारी या पुलिस को सूचना नहीं देता है, तो वह दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

22. जो कोई भी, श्रीषधियों या चिकित्सीय उपकरणों की खरीद के लिए उत्तरदायी होते हुए, कपटपूर्वक घटिया किसम की या अप्रमाणिक या विनिर्देश से निम्न स्तर की श्रीषधियों और उपकरणों की खरीद करता है तो उसे दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि कम से कम एक वर्ष की होगी, किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डित किया जायेगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा:

परन्तु न्यायालय अभिलिखित विशेष कारणों से एक वर्ष से कम अवधि के कारावास का दण्डादेश भी अधिरोपित कर सकेगा।

अध्याय 5

मानवीय उपभोग के लिए अनुपयुक्त शराब की बिक्री से सम्बन्धित अपराध

मानवीय उपभोग के लिए अनुपयुक्त शराब की बिक्री शराब की बिक्री की जांच करने और रोकने के लिए अनुपयुक्त शराब की बिक्री के अपराध की जांच और रिपोर्ट नहीं करता है या उसकी मौतानुमति देता है या उसे दुष्प्रेरित करता है तो वह दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

अध्याय 6

कर से बचने के लिए बोगस फर्मों के पंजीकरण से सम्बन्धित अपराध

24. जो कोई भी, विक्री कर से बचने या दुस्संबंधिपूर्ण बोली देने, या दुस्संबंधिपूर्ण निविदा प्रस्तुत करने के लिए छल करने के प्रयोजनार्थ बोगस या अविद्यमान फर्म के पंजीकरण के लिए आवेदन करता है या बोगस या अविद्यमान फर्म के नाम का प्रयोग करता है तो वह दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

25. जो कोई भी, अधिकारी होते हुए, आशय से, जानवृक्ष कर या उपेक्षा से, समुचित जांच किये बिना, धारा 24 के अधीन अपराध को दुष्प्रेरित करने के आशय से किसी बोगस फर्म को पंजीकृत करता है या बोगस या अविद्यमान फर्म के नाम का उपयोग करने की अनुमति देता है, तो वह दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

बोगस फर्मों नाम के प्रयोग या पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए दण्ड।

बोगस फर्मों के पंजीकरण करने या धारा 24 के अधीन अपराध को दुष्प्रेरित करने के लिए दण्ड।

काल्पनिक दस्तावेजों और बिना निधि के चैक के प्रस्तुती करण के लिए दण्ड।

1968 का 24 26. जो कोई भी, हिमाचल प्रदेश सामान्य विक्री कर अधिनियम, 1968, हिमाचल 1968 का 10 प्रदेश मोटर स्पिरिट (विक्री कराधान) अधिनियम, 1968, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 का 74 1956 और हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा वहन किये गये सामान पर) कराधान 1976 का 34 अधिनियम, 1976 के अधीन देय कर या हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा प्रवृत्त पंजाब 1914 का 1 आबकारी अधिनियम, 1914 के अधीन देय किसी शुल्क या फीस के प्रयोजनार्थ, आशय से या जानवृक्ष कर—

- (1) उक्त अधिनियमितियों के अधीन के कर, शुल्क या फीस से बचने के लिए छल साधन के प्रयोजनार्थ कोई मिथ्या या काल्पनिक दस्तावेज या घोषणा देता है या प्रस्तुत करता है; या
- (2) ऐसा चैक देता है जिसका उसके लेखे में निधि की कमी के कारण अनादर किया जाये,

तो उसे, दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

27. जो कोई भी, किसी चैक-पोस्ट या बैरिंगर का प्रभारी अधिकारी या धारा 26 में निर्दिष्ट कर शुल्क या फीस को प्रभारित करने के लिए कर्तव्यबद्ध कोई पदधारी होते हुए, आशय से या जानवृक्ष कर इस अधिनियम की धारा 26 के अधीन अपराध को दुष्प्रेरित करने के आशय से ऐसे कर, शुल्क या फीस को प्रभारित नहीं करता है या उक्त अधिनियमिति के प्रयोजन के लिए मिथ्या या काल्पनिक दस्तावेज या किसी घोषणा की अनुमति देता है या ऐसे कर, शुल्क या फीस से बचने के लिए छल साधन को मौनानुमति देता है या दुष्प्रेरित करता है, तो वह दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि कम से कम एक वर्ष होगी, किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डित किया जायेगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा:

परन्तु न्यायालय अधिकारित विशेष कारणों से एक वर्ष से कम अवधि के कारावास का दण्डादेश भी अधिरोपित कर सकेगा।

अध्याय 7

काल्पनिक क्रृष्ण और उनके उपयोग के मिथ्या सत्यापन और भूमि के अधिकमण से सम्बन्धित अपराध

काल्पनिक व्यक्तियों को अधिकारी होते हुए आशय से या जानबूझ कर या भ्रष्ट हेतु से या अन्यथा,— क्रृष्ण देने के लिए दण्ड।

(क) किसी काल्पनिक नाम से, या

(ख) किसी काल्पनिक या अविद्यमान व्यक्ति को, या

(ग) किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर,

क्रृष्ण या अर्थसाहाय्य स्वीकृत करता या देता है या जो कोई भी क्रृष्ण या अर्थसाहाय्य की ऐसी स्वीकृति या उसके दिये जाने का वास्तविक लाभ प्राप्त करता है तो वह दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमाने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

क्रृष्ण के उपयोग के मिथ्या सत्यापन के लिए दण्ड।

29. जो कोई भी, क्रृष्ण या अर्थ-साहाय्य के समुचित उपयोग का सत्यापन करने और उसके सम्बन्ध में रिपोर्ट करने के लिए कर्तव्यबद्ध होते हुए, जिस प्रयोजन से वह क्रृष्ण स्वीकृत किया गया या दिया गया हो, उसके प्रसंग में, उसके समुचित उपयोग के सम्बन्ध में मिथ्या रिपोर्ट या सत्यापन करता है या प्रमाणित करता है, जबकि वास्तव में उस प्रयोजन से उसका पूर्ण उपयोग नहीं किया गया हो या अंशतः उपयोग किया गया हो, या उपयोग बिलकुल ही नहीं किया गया हो, वह यदि उक्त क्रृष्ण या अर्थ-साहाय्य उसे स्वीकृत करने या देने वाले प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से किसी अन्य प्रयोजन में नहीं लगाया गया हो, तो वह दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमाने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

अधिकमण का पता लगाने और रिपोर्ट करने की असफलता के लिए दण्ड।

30. जो कोई भी —

- (1) आरक्षित और सीमांकित संरक्षित वनभूमि के अधिकमण को रोकने के लिए कर्तव्यबद्ध वन विभाग का अधिकारी होते हुए, या
- (2) सरकारी भूमि के अधिकमण को रोकने के लिए कर्तव्यबद्ध राजस्व विभाग का अधिकारी होते हुए, या
- (3) नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति, या नगरपालिका का, इन निकायों की भूमि के अधिकमण को रोकने के लिए, कर्तव्यबद्ध अधिकारी होते हुए,

आशय से या जानबूझ कर उसके अधिकारिता क्षेत्र में किसी अधिकमण की अनुज्ञा देता है, मौनानुमति देता है या दुष्प्रेरणा करता है या पता लगाने या रिपोर्ट करने में अपनी चक्र के कारण उसे होने देता है, तो वह दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि कम से कम एक वर्ष तक की होगी, किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डित किया जाएगा और जुमाने के लिए भी दायी होगा :

परन्तु न्यायालय अभिलिखित विशेष कारणों से एक वर्ष से कम अवधि के कारावास का दण्डादेश भी अधिरोपित कर सकेगा।

अध्याय 8

जन-वितरण प्रणाली में गड़बड़ी करने से सम्बन्धित अपराध

1955 का 10. 31. जो कोई भी आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन निर्णय किसी आदेश के अधीन अनुज्ञाप्त व्योहारी होते हुए, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन घोषित आवश्यक वस्तुओं को, जैसे राज्य सरकार अधिसचना द्वारा इस अध्याय के प्रयोजन के लिये विनिष्ट करे, जन-वितरण प्रणाली स्कौम के अनुसार, सम्बद्ध जनता को आपूरित करने के बदले आशय से, जानबूझ कर या छष्ट हेतु से ऐसी आवश्यक वस्तुओं को अन्य माध्यमों में अंतरित करता है या उनके वितरण का मिथ्या या काल्पनिक लेखा रखता है तो वह दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

अनुज्ञाप्त अधीन व्योहारी द्वारा जन-वितरण प्रणाली में गड़बड़ी।

32. जोकोई भी, जन-वितरण प्रणाली के समुचित कार्य-चालन के पर्यवेक्षण का प्रत्यक्षतः या मुख्यतः प्रभारी अधिकारी होते हुए, धारा 31 के अधीन दण्डनीय अपराध की जांच और रिपोर्ट करने में जानबूझ कर चक करता है या उसकी मौनानुमति देता है या उसे दुष्प्रेरित करता है, तो वह दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

किसी अधिकारी द्वारा धारा 31 के अधीन अपराध का दुष्प्रेरण।

अध्याय 9

प्रक्रीण उपबन्ध

33. जो कोई भी अधिकारी होते हुए, जानबूझ कर कर्तव्य से अपनी अप्राधिकृत अनुपस्थिति की अवधि के लिए, जब तक कि वह अवधि अनुमति की स्वीकृति या सबेतन अवकाश को स्वीकृति द्वारा नियमित न कर दी गई हो, अपना वेतन स्वयं आहरण करता है या अपनी अनुपस्थिति से सम्बन्धित तथ्यों को छुपा कर या उनका अन्यथा गलत विवरण देकर आदान तथा संवितरण अधिकारी को अपना वेतन आहरण और संवितरित करने की अनुज्ञा देता है या उत्प्रेरित करता है, और इस प्रकार सरकार के साथ छल करता है, तो वह दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए वेतन आहरण करने के लिए दण्ड।

1974 का 2. 34. इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 के अधीन निर्णय किसी सरकारी सेवक के अभियोजन की स्वीकृति, जो सम्यक रूप से अधिप्रमाणित और सीलकृत तात्पर्यित हो, बिना किसी औपचारिक सबूत के साक्ष्य में ग्राह्य होगी:

स्वीकृति का सबूत।

परन्तु यदि अपराध से सम्बन्धित तथ्यों का स्वीकृति पत्र देखने से पता न चले, तो न्यायालय स्वीकृति को अधिप्रमाणित करने वाले अधिकारी को अपने सामने साझा देने के लिए बुला सकेगा।

1974 का 2. 35. राज्य के कार्यकालापों के सम्बन्ध में नियोजित किसी व्यक्ति के अभियोजन के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 के अधीन दी गई औपचारिक स्वीकृति में कोई तकनीकी त्रुटि होने से विचारण तब तक दूषित नहीं होगा जब तक कि यह साबित न कर दिया जाए कि इससे अभियुक्त पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

स्वीकृति प्ररूप म तकनीकी त्रुटियों का दूर किया जाना।

अपराध का
संज्ञान।
अध्याय 3
के अधीन के
अपराधों के
सिवाय अन्य-
अपराध
जमानतीय
होंगे।

अपराध सत्त-
न्यायालय
द्वारा विचार-
णीय होंगे।

उपबंध कर्ति-
पय विधियों
के अल्पी-
करण में नहीं
होंगे।

नियम बनाने
की शक्ति।

36. इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी अपराध का कोई भी न्यायालय तब तक संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के जरिए विनिर्दिष्ट अधिकारी ने लिखित रिपोर्ट न की हो:

परन्तु राज्य की न्यायिक सेवा के किसी सदस्य के विरुद्ध ऐसी रिपोर्ट उच्च न्यायालय की पूर्व सहमति के बिना नहीं की जाएगी।

37. अध्याय 3 के अधीन किए गए अपराधों के सिवाए, जो अजमानतीय होंगे, इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराध जमानतीय होंगे।

38. इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का, मुपुर्दगी के पश्चात्, सत्र-न्यायालय द्वारा विचारण किया जाएगा।

39. इस अधिनियम के उपबंध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947, भारतीय दण्ड संहिता, 1860, भारतीय बन अधिनियम, 1927, हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा के अल्पी- प्रवक्त पंजाब ग्राबकारी अधिनियम, 1914, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और दण्ड करण में नहीं प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, त कि उनके अल्पीकरण में होंगे।

40. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के समझ, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में अधवा दो अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, और यदि उस सत्र के, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया था या ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व सदन उस नियम में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत हो जाये या सदन सहमत हो जाए कि यह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, और ऐसा विनिश्चय राजपत्र में अधिसूचित किया जाए, तो नियम ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु नियम के ऐसे उपान्तरण या निष्प्रभावन से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

41. (1) हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट ग्राचरण अध्यादेश, 1983 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी यह कि उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जायेगी भानोकि उस दिन जिस दिन ऐसी बात या कार्रवाई की गई थी यह अधिनियम लागू हो चुका था।

1947 का 2
1860 का 45
1927 का 100
1914 का 1
1955 का 10
1974 का 2

1983 का 7

[Authoritative English text of the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983 (No. 3 of 1984) as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

Act No. 3 of 1984.

THE HIMACHAL PRADESH PREVENTION OF SPECIFIC CORRUPT PRACTICES ACT, 1983

AN

ACT

to provide for punishment of specific corrupt practices resorted to by the persons serving in connection with the affairs of the State or of public undertakings or local authorities, co-operative societies or other institutions or organisations aided or set up by State Government and by some other persons in their dealings with the State Government and aforesaid bodies, with a view to eradicate and effectively prevent such practices and for other miscellaneous matters connected therewith.

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Thirty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983.

Short title,
extent and
commencement.

(2) It shall extend to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force with effect from the 28th day of October, 1983.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

Definitions.

(a) “local authority” means any public undertaking, authority, co-operative society, corporation, body, board, society or organisation, by whatever name they are known,—

(i) incorporated or set up by the State Government, or

(ii) constituted under any Law, Ordinance, Act, Rules, or Regulations of the State Government, or

(iii) constituted under any Central Act, Ordinance, Rules, or Regulations, over which the State Government has control and authority;

(b) “officer” means a person serving in connection with the affairs of the State, local authority, or any other institution or organisation aided or set up by the State Government;

- (c) "public undertaking" means a Government Company, within the meaning of section 617 of the Companies Act, 1956, in which not less than fifty-one per cent of the paid up share capital is held by the State Government or any Company which is a subsidiary of a Company in which not less than fifty-one per cent of the paid up share capital is held by the State Government and includes a corporation or other statutory body, by whatever name called, in each case owned or controlled by the State Government and any other Government Company, other than a Company owned and controlled by the Central Government in which the State Government has contributed equity.

CHAPTER II

OFFENCES RELATING TO WORK

Definitions.

3. In this Chapter, unless the context otherwise requires,—

- (a) "construction" means all activities pertaining to the construction of a work and includes excavation, filling, levelling and other allied activities;
- (b) "contractor" in relation to a work means a person who undertakes to execute the work under a works department, in pursuance of a contract and includes, where the context so requires, a sub-contractor and includes, all other agencies and persons employed by him or working under his control for the execution of such work and the expression "works contract" shall be construed accordingly;
- (c) "officer-in-charge" means an officer in relation to a work under a works contract who is primarily and directly responsible on the work site to see that the work or specific part of the work is duly executed in accordance with the terms, conditions and specifications of the works contract and the instructions, directions or work order issued, by the supervisory officers or by the works department, from time to time;
- (d) "officer of the works department" means the officer, whatever be the designation, employed in the works department and concerned with the survey, construction, repairs, maintenance, supervision, planning, drawing, designing, purchase, supply or storage of goods, mechanically propelled or electrically operated vehicles of all descriptions, plants, machinery, tools, spares or all officials responsible to make payment of bills and advances, in relation to the work;
- (e) "supervisory officer" means an officer whose duty it is to supervise the work as per instructions contained in the Manual applicable to the works department or contained in any order or direction issued by the works department, from time to time;
- (f) "work" means any work relating to survey, construction, repairs or maintenance of any building, superstructure, dam, weir, canal, reservoir, tank, lake, road, bridge, culvert, well including tube-well, factory, workshop, water supply system, electric installation system or any other work which the State Government may by notification specify in this behalf and includes surveying, planning, drawing, designing, purchase, supply or storage of goods, mechanically propelled or electrically operated vehicles of all descriptions,

plant, machinery, tools, spares or all other materials and equipments relating to the construction, maintenance or repairs of any of the aforesaid works;

(g) "works department" means a department of the State Government, a public undertaking, a local authority, or a co-operative society registered under the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968, which gives a works contract or under whose orders, directions or control works contract is entered into or work is done, and shall include—

(i) an institution or organisation substantially aided by the State Government, as the State Government may, by notification, specify, and

(ii) any statutory or non-statutory body, by whatever name called, incorporated or set up by the State Government.

4. Whoever, being a contractor of a works contract entered into with a works department, intentionally, knowingly or for corrupt motive executes the work in material violation of the terms of the contract or in flagrant disregard of the standards, specifications, orders or directions given by the works department, or its officers, so as to adversely affect the quality, workmanship, strength or life of the work or part of it, shall be punished with imprisonment of either description which may extend to three years, or with fine, or with both.

Punishment
to contractor
for violation
of contract,
etc.

5. Whoever, being an officer-in-charge of a work under a works contract being executed by a contractor or otherwise, intentionally or knowingly—

(a) permits or connives at, or

(b) omits to prevent or to report about, or

(c) abets for corrupt motive,

the work being done in—

(i) material violation of the terms of the contract, or

(ii) flagrant disregard of the standard specifications, orders or directions given by the works department or its officers,

in either case so as to adversely affect the quality, workmanship, strength or life of the work or part of it, shall be punished with imprisonment of either description which may extend to three years, or with fine, or with both.

Punishment
to officer-in-
charge for
lack of
supervision.

6. (1) Whoever, being an officer-in-charge of a work or being an officer of the works department, in connection with a work, intentionally or knowingly—

(a) prepares a false or fictitious muster-roll, or

(b) prepares a false or fictitious measurement book, or

(c) makes payment for false or fictitious lead for false or fictitious excavation of metal, sand, earth, or

(d) incorrectly classifies a strata under excavation for making payment at a higher rate, or

(e) pays for no work or inadequate or for fictitious or bogus work, or

(f) pays at rates that are grossly inappropriate or makes deliberate overpayments, in violation of rules and orders,

shall be punished with imprisonment of either description which may extend to three years, or with fine, or with both.

Punishment
for prepar-
ing false or
fictitious
muster-rolls
or measure-
ment books.

(2) Whoever, being a supervisory officer, abets the commission of an offence under sub-section (1), shall also be punished with imprisonment of either description which may extend to three years, or with fine, or with both.

Punishment for surreptitious sale of supplied material by contractor.

Punishment for submitting manipulated tenders.

7. Whoever, being a contractor under a works contract, sells or otherwise transfers cement, steel, iron, or any other material supplied by the works department for the work as per specifications, instead of properly utilising the same in the work or instead of returning the unused or excess material back to the works department, shall be punished with imprisonment of either description which may extend to three years, or with fine, or with both.

8. Whoever, being a tenderer for a work under a works department,—
 (a) procures, obtains or attempts to procure or obtain for himself or for any other person work under a works contract by submitting fictitious competitive tenders in the name of false or non-existent or bogus person, or
 (b) enters into a conspiracy with any other tenderer or tenderers in order to eliminate the competition for the purpose of pushing one of the collusive low-rate tender for acceptance, or
 (c) employs or takes active help of a near relative or of any other person in a position to unduly influence the officer having authority to accept the tender,

shall be punished with imprisonment of either description which may extend to three years, or with fine, or with both.

Explanation.—Near relation in this section means son, grand-son, father, mother, spouse, brother, sister, brother-in-law, father-in-law and mother-in-law.

Punishment to officer for accepting manipulated tender.

9. Whoever, being an officer of a works department, having authority to accept a tender on behalf of a works department—

(a) abets the commission of an offence under section 8 by accepting or recommending for acceptance such tender, or
 (b) dishonestly manipulates evaluation of tenders with the object of giving benefit to a particular tenderer,

shall be punished with imprisonment of either description which may extend to three years, or with fine, or with both.

Punishment for wrongful or unauthorised disposal of property.

10. Whoever, being an officer of a works department, dishonestly, wrongfully or fraudulently—

(a) disposes of or otherwise transfers; or
 (b) permits unauthorised use of goods, plants, machinery, tools, spares or other material and equipments from the stores, causing substantial loss to the works department,

shall be punished with imprisonment of either description which may extend to three years, or with fine, or with both.

Punishment for supply of sub-standard or lesser quantity of goods.

11. Whoever, being a contractor for the supply of goods, plants, machinery, tools, spares or other materials or equipments—

(a) makes misrepresentation in respect to the quantity supplied, or
 (b) supplies sub-standard goods, plants, machinery, tools, spares or other materials or equipments which are not of mercantile quality or not in accordance with the samples or specifications given in the order of supply,

shall be punished with imprisonment of either description which may extend to three years, or with fine, or with both.

12. Whoever, being an officer of a works department, having authority to accept the supplies made by the contractor in pursuance of an order of supply given to him, abets the offence punishable under section 11 knowingly by accepting the supply of goods, plants, machinery, tools, spares or other materials or equipments shall be punished with imprisonment of either description which may extend to three years, or with fine, or with both.

Punishment to officer of works department for abetting offences under section 11.

13. Whoever, being an officer of the works department, with *mala fide* intention, resorts to splitting of purchase order in order to enable him to affect the purchases which would have otherwise been beyond the pale of his financial authority to do so, or in flagrant breach of the established procedure for the purchase of goods, plants, machinery, tools, spares or other materials or equipments shall be punished with imprisonment of either description which may extend to one year, or fine, or both.

Punishment for splitting up purchase orders.

CHAPTER III

OFFENCES CONNECTED WITH THE PRESERVATION OF FORESTS AND WILD LIFE

14. Whoever, being an officer-in-charge for the preservation and maintenance of forest or disposal of forest produce, having jurisdiction intentionally or knowingly permits, connives or abets or fails to report, the—

Punishment for illicit felling or disposal of forest produce.

(i) illegal felling of trees or extraction of logs, or

(ii) illegal girdling or trapping, or

(iii) theft of wood, timber or bamboos, or other forest produce,

for commercial purpose shall be punished with imprisonment of either description which shall not be less than one year but which may extend to three years, and shall also be liable to fine:

Provided that the court may, for any special reason to be recorded in writing, impose a sentence of imprisonment of less than one year.

15. Whoever trades in any forest produce and is or has been in possession of that produce which he cannot satisfactorily account for shall be punished with imprisonment of either description which shall not be less than one year but which may extend to three years, and shall also be liable to fine:

Punishment for trading in certain forest produce unaccounted for.

Provided that the court may, for any special reason to be recorded in writing, impose a sentence of imprisonment of less than one year.

*Explanation.—*For the purpose of this section,—

(a) “forest produce” means “timber” and “trees” as defined in clauses (6) and (7) of section 2 of the Indian Forest Act, 1927 and shall include resin, catechu or any other forest produce, which the State Government may, by notification, specify in this behalf; and

(b) “trading in forest produce” means the sale or purchase of any forest produce in any manner, shape or form, whatever, or carrying on any business in it with a view to make profit.

Punishment for falsification of bid-sheets and manipulation of transit passes.

16. Whoever, being an officer,—

- (i) manipulates bid-sheets in relation to auction of forest produce, or
- (ii) manipulates issue of fictitious transit passes with a view to give benefit to any person or for causing wrongful loss to the Government Department,

shall be punished with imprisonment of either description which may extend to three years, or with fine, or with both.

Punishment for wrong-ful demar-
cation of
forest lands.

17. Whoever, being an officer responsible for giving demarcation of boundaries of private and Government forests for the purpose of felling of trees in the private forests or for any other purpose intentionally or knowingly gives wrong demarcation so as to cause loss to the Government shall be punished with imprisonment of either description which shall not be less than one year but which may extend to three years and shall also be liable to fine:

Provided that the court may, for any special reason to be recorded in writing, impose a sentence of imprisonment of less than one year.

Punishment for illegal hunting or extinction of wild life.

18. Whoever, being an officer duty bound to preserve and protect wild life,—

- (a) commits, permits, connives or abets illegal hunting of wild animals; or
- (b) gives shelter to the poachers; or
- (c) helps in arranging drives of animals or putting fire to wild animals habitats with a view to herding for easy hunting; or
- (d) conceals information or fails to report illegal hunting of wild animals or illegal possession of animal articles or trophies of wild animals mentioned in Schedule I of the Wild Life Protection Act, 1972,

shall be punished with imprisonment of either description which shall not be less than one year but which may extend to three years and shall also be liable to fine:

Provided that the court may, for any special reason to be recorded in writing, impose a sentence of imprisonment of less than one year.

CHAPTER IV

OFFENCES RELATING TO HOSPITALS, ETC.

Punishment for misappropriation or removal of medicines or equipment.

19. Whoever, being an officer duty bound to maintain stock register, bills or vouchers of medicines or medical equipment in a Government hospital, dispensary or any other such institution or centre, organised and assisted by the Government, mis-appropriates or fraudulently removes medicines or medical equipment or intentionally or knowingly permits, connives or abets such mis-appropriation or removal, shall be punished with imprisonment of either description which shall not be less than one year and it may extend to three years and shall also be liable to fine:

Provided that the court may, for any special reason to be recorded in writing, impose a sentence of imprisonment of less than one year.

20. Whoever, being a medical officer, compounder, dresser or nurse on duty or any other employee of a Government hospital, dispensary or any other such institution or centre, organised and assisted by the Government, absents himself or herself from duty without reasonable cause and without due intimation to the authority or fraudulently or unauthorisedly charges fees from any person for his treatment therein shall be punished with imprisonment of either description which may extend to one year, or with fine, or with both.

Punishment for absence from duty or fraudulently or unauthorisedly charging fees.

21. Whoever, being duty bound to prepare injury report or post-mortem report or bed-head ticket of the patient, fraudulently prepares the same incorrectly or intentionally omits to mention all the details or does not inform the authority or the Police, where he is so required to inform under the rules or regulations or Government orders or circulars, shall be punished with imprisonment of either description which may extend to one year, or with fine, or with both.

Punishment for failure to maintain record properly.

22. Whoever, being responsible for the purchase of medicines or medical equipments fraudulently purchases medicines or equipments which are sub-standard or spurious or below specification shall be punished with imprisonment of either description which shall not be less than one year but which may extend to three years and shall also be liable to fine:

Punishment for fraudulent purchases of medicines.

Provided that the court may, for any special reason to be recorded in writing, impose a sentence of imprisonment of less than one year.

CHAPTER V

OFFENCES RELATING TO SALE OF LIQUOR UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION

23. Whoever, being duty bound to check and prevent the sale of illicit liquor, knowingly omits to check and report, connives or abets the commission of offence of sale of illicit liquor shall be punished with imprisonment of either description which may extend to three years, or with fine, or with both.

Punishment for sale of liquor unfit for human consumption and failure to check sale of illicit liquor.

CHAPTER VI

OFFENCES RELATING TO REGISTRATION OF BOGUS FIRMS FOR TAX EVASION

24. Whoever, applies for the registration of a bogus or non-existent firm, or uses a bogus or non-existent firm name, for the purpose of manipulating sales-tax evasion, or for collusive bidding, or for submitting collusive tender, shall be punished with imprisonment of either description which may extend to three years, or with fine, or with both.

Punishment for applying for registration of or use of bogus firm name.

25. Whoever, being an officer-intentionally, knowingly or negligently, without holding proper inquiry, registers a bogus firm or permits the use of bogus or non-existent firms name, with the intention to abet the offence under section 24, shall be punished with imprisonment of either description which may extend to three years, or with fine, or with both.

Punishment for registering bogus firms for abetting offences under section 24.

Punishment for production of fictitious documents and cheque without funds.

26. Whoever, for the purposes of the tax payable under the Himachal Pradesh General Sales Tax, Act, 1968, the Himachal Pradesh Motor Spirit (Taxation of Sales) Act, 1968, the Central Sale Tax Act, 1956, and the Himachal Pradesh Taxation (On Certain Goods Carried by Road) Act, 1976, or any duty or fee under the Punjab Excise Act, 1914, as in force in the State of Himachal Pradesh, intentionally or knowingly,—

- (i) furnishes or produces a false or fictitious document or declaration, with a view to manipulating evasion of taxes, duties or fees under the said enactments; or
- (ii) tenders a cheque which is dishonoured due to lack of funds in his account,

shall be punished with imprisonment of either description which may extend to one year, or with fine, or with both.

Punishment to officers for non-collection of taxes and for facilitating tax evasion.

27. Whoever, being an officer-in-charge of check-post or barrier or an official duty-bound to charge the tax, duty or fee referred to in section 26, intentionally or knowingly does not charge such tax, duty or fee, or allows any false or fictitious document or a declaration for the purposes of the said enactments with the intention to abet an offence under section 26 of this Act or connives or abets the manipulation of evasion of such tax, duty or fee, shall be punished with imprisonment of either description which shall not be less than one year but which may extend to three years and shall also be liable to fine:

Provided that the court, may, for any special reason to be recorded in writing, impose a sentence of imprisonment of less than one year.

CHAPTER VII

OFFENCES RELATING TO FICTITIOUS LOAN AND FALSE CERTIFICATION OF THEIR UTILIZATION AND ENCROACHMENT OF LANDS

Punishment for advancing loans, etc. to fictitious persons.

28. Whoever, being an officer having authority to sanction or advance loan or subsidy intentionally, knowingly, or for corrupt motive or otherwise, sanctions or advances loan or subsidy—

- (a) in a fictitious name, or
- (b) to a fictitious or non-existing person, or
- (c) in the name of another person,

and whoever received actual benefit of such sanction or advance of the loan or of subsidy, shall be punished with imprisonment of either description which may extend to three years, or with fine, or with both.

Punishment for false verification of loan utilisation.

29. Whoever, being under a duty to verify and report proper utilisation of a loan or subsidy, falsely reports, verifies to testifies to the proper utilisation thereof, with reference to the purpose for which it was sanctioned or advanced, when in fact it was not so utilised fully, or was utilised only partly, or was not utilised at all, in relation to that purpose, unless it was diverted to some other purpose with the prior sanction of authority which sanctioned or advanced the loan or subsidy, shall be punished with imprisonment of either description which may extend to one year, or with fine, or with both.

24 of 1968.
10 of 1968.
74 of 1956.
34 of 1976.
1 of 1914.

30. Whoever,—

- (i) being an officer of the Forest Department duty bound to prevent an encroachment over the reserved and demarcated protected forest land ; or
- (ii) being a revenue officer duty bound to prevent any encroachment over land belonging to the Government; or
- (iii) being an officer of the Municipal Corporation Notified Area Committee or Municipal Committee, duty bound to prevent encroachment over the land belonging to these bodies, intentionally or knowingly permits, connives, abets or suffers on account of his omission to detect or report an encroachment in areas within his jurisdiction shall be punished with imprisonment of either description which shall not be less than one year but which can be extended to three years and shall also be liable to fine:

Punishment for failure to detect and report encroachment.

Provided that the court may, for any special reason to be recorded in writing impose a sentence of imprisonment of less than one year.

CHAPTER VIII

OFFENCES RELATING TO TAMPERING WITH THE PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM

31. Whoever, being a dealer licensed under any order issued under section 3 of the Essential Commodities Act, 1955, instead of supplying the essential commodity declared by or under the said Act, as the State Government may, by notification, specify for the purpose of this Chapter, to the public concerned in accordance with the scheme of the public distribution system intentionally, knowingly or for corrupt motives, transfers such essential commodity to other channels or maintains false or fictitious account for the distribution of the same, shall be punished with imprisonment of either description which may extend to three years, or with fine, or with both.

Tampering with the systems by the licensed dealer.

32. Whoever, being an officer, directly or primarily in-charge of supervision for the proper working of public distribution system, knowingly omits to check and report, connives or abets the commission of the offence punishable under section 31 shall be punished with imprisonment of either description which may extend to three years, or with fine, or with both.

Abetment of offences under section 31 by an officer.

CHAPTER IX

MISCELLANEOUS PROVISIONS

33. Whoever, being an officer intentionally draws himself or, by suppression of facts or otherwise, misrepresenting the facts relating to his absence, permits or induces the drawing and disbursing officer to draw and disburse the salary to him for the period of his deliberate unauthorised absence from duty, unless the same is regularised by grant of permission or sanction of leave with pay, and thereby cheats the Government shall be punished with imprisonment of either description which may extend to one year, or fine, or both.

Punishment for drawing salary for the period of absence from duty.

34. The sanction for prosecution of a Government servant for an offence under this Act, issued under section 197 of the Code of Criminal Procedure, 1973, and purporting to be duly authenticated, and sealed shall be admissible in evidence without formal proof:

Proof of sanction.

Provided that where the facts constituting the offence do not appear on the face of the sanction, the court may call the officer authenticating the sanction to give evidence before it.

35. Any technical defect in the formal sanction granted under section 197 of the Code of Criminal Procedure, 1973 for the prosecution of a person employed in connection with the affairs of the State shall not vitiate the trial unless it is proved that it caused substantial prejudice to the accused.

Cognizance of offences. 36. No court shall take cognizance of an offence under this Act against any person unless a report in writing is made by such an officer of the State Government as it may, by a notification, specify:

Provided that no such report shall be made against a member of judicial service of State save with the prior concurrence of the High Court.

Offences to be bailable, except under Chapter III. 37. An offence under this Act, shall be bailable except offences under Chapter III which shall be non-bailable.

Offences to be triable by a Court of Sessions. 38. An offence under this Act shall, on commitment, be tried by a Court of Sessions.

Provisions not to be derogatory to certain Laws. 39. The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of the Prevention of Corruption Act, 1947, the Indian Penal Code, 1860, the Indian Forest Act, 1927, the Punjab Excise Act, 1914, as in force in the State of Himachal Pradesh, the Essential Commodities Act, 1955 and the Code of Criminal Procedure, 1973.

2 of 1947
45 of 1860
16 of 1927
1 of 1914
10 of 1955
2 of 1974

Power to make rules. 40. (1) The State Government may, by notification, make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislature while it is in session for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or two successive sessions, and if before the expiry of the session in which it is so laid, or the session immediately following, the House agrees in making any modification in the rule or the House agrees that the rule should not be made, and such decision is notified in the Official Gazette, the rule shall from the date of publication of such notification, have effect only in such modified form or be of no effect as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

7 of 1983

41. (1) The Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Ordinance, 1983 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done, or taken, under the corresponding provisions of this Act, as if this Act had come into force on the day on which such thing was done or action was taken.